



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन जन. गण., तथा ब्राजील के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित इथिलीन-प्रोपीलीन-असंबद्ध डियन रबड़ (ईपीडीएम) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत।

सं. 15/2/2009-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन जन. गण. तथा ब्राजील (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित इथिलीन-प्रोपीलीन-असंबद्ध डियन रबड़ (ईपीडीएम) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 15 जून, 2006 की अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी जो दिनांक 16 जून, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित हुई थी, के तहत अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

और यतः संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 19 जुलाई, 2006 की सी.शु. अधिसूचना सं. 75/2006-सी.शु. के तहत लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जाँच और वर्तमान समीक्षा आवेदन में शामिल विचाराधीन उत्पाद यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन. जन. गण. तथा ब्राजील के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित "इथिलीन-प्रोपीलीन-असंबद्ध डियन रबड़ (ईपीडीएम)" है। संबद्ध वस्तुएँ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत छह अंकीय स्तर पर उपशीर्ष सं. 4002.70 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और प्रस्तावित जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इथिलीन-प्रोपीलीन-असंबद्ध डियन रबड़ (ईपीडीएम) है। ईपीडीएम एक सिंथेटिक रबड़ है और ईपीडीएम के तकनीकी विनिर्देशन मोटे तौर पर इथिलीन, प्रोपीलीन तथा डियन की मात्रा एवं मूनी श्यानता द्वारा नियंत्रित होती हैं। इथिलीन, प्रोपीलीन तथा डियन

की मात्रा एवं मूनी श्यानता में परिवर्तन करके ईपीडीएम रबड़ की विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन किया जा सकता है।

ईपीडीएम रबड़ का उपयोग मुख्यतः रबड़ प्रोफाइलों, ऑटोमोटिव टायरों तथा ट्यूबों, केबलों, हौजों एवं ऑटोमोबाइल पूजों में प्रयुक्त मोल्डेड वस्तुओं में किया जाता है। इथिलिन, प्रोपीलीन तथा डियन की मात्रा एवं मूनी श्यानता तथा अन्य विशेषताओं में परिवर्तन करके सामान्य गुणधर्मों में केवल संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए ईपीडीएम का प्रयोग किया जाता है। ईपीडीएम रबड़ विभिन्न ग्रेडों का हो सकता है और इसकी आपूर्ति विभिन्न रूपों में की जा सकती है। इस जाँच में सभी ग्रेडों एवं रूपों के सभी ग्रेडों के इथिलीन-प्रोपीलीन-असंबद्ध डियन रबड़ (ईपीडीएम) को शामिल किया गया है।

3. जाँच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 एवं उसके तहत बनाए गए पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर जाँच करने की अपेक्षा की गई है। ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि ईपीडीएम प्रमुख कच्चे माल में से एक है जिसका उपयोग टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यद्यपि इस उत्पाद के एकमात्र विनिर्माता अर्थात् मै. यूनीमर्स इंडिया लि. ने फरवरी-मार्च, 2007 से इसका उत्पादन स्थगित कर दिया है और इसका उत्पादन बहाल होने की कोई संभावना नहीं है, तथापि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क अभी भी लगा हुआ है, जिससे टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है। उपर्युक्त को देखते हुए उन्होंने ईपीडीएम से पाटनरोधी शुल्क तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया है।

मै. यूनीमर्स इंडिया लि. ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने ईपीडीएम रबड़ का उत्पादन बंद कर दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26.06.2008 से अपनी फैक्टरी को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है।

उपर्युक्त स्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी का मत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के प्रावधान और यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के अंतर्गत इस स्थिति में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना समुचित होगा।

4. शामिल देश

मौजूदा जाँच में शामिल देश यूरोपीय संघ, यूएसए, चीन जन. गण. तथा ब्राजील हैं।

5. समीक्षा हेतु आधार

याचिकाकर्ताओं अर्थात् ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपनी याचिकाओं में यह दावा किया है कि ईपीडीएम के एकमात्र विनिर्माता अर्थात् मै. यूनीमर्स इंडिया लि. ने लंबे समय से उत्पादन बंद कर दिया था और टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र के लिए ईपीडीएम के एक महत्वपूर्ण सामग्री होने के कारण संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए ताकि टायर तथा गैर-टायर उत्पादों की लागत पर पड़ने वाले अनावश्यक क्रमिक प्रभाव को रोका जा सके। आगे, मै. यूनीमर्स इंडिया लि.,

मुंबई ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने ईपीडीएम खड़ का उत्पादन बंद कर दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26.06.2008 से अपनी फैक्टरी को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर प्रभावी पाटनरोधी उपायों की समीक्षा अनिवार्य है।

6. प्रक्रिया

आवेदकों द्वारा परिवर्तित स्थितियों जिनके कारण प्रभावी उपायों की समीक्षा अनिवार्य हो गई है, को दर्शाते हुए दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार परिवर्तित स्थितियों के मद्देनजर उपर्युक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9(क) के प्रावधान के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड I में दिनांक 16 जून, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम परिणाम तथा 19 जुलाई, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 75/2006 द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना अब समुचित है। समीक्षा में दिनांक 15.06.2006 की अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी के सभी पहलु शामिल हैं।

7. जांच की अवधि

वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2008 (12 महीने) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण की अवधि में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं जांच की अवधि शामिल होगी।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र एवं पद्धति में नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकती है।

9. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से “चालीस दिनों” के भीतर पहुंच

मुंबई ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने ईपीडीएम खड का उत्पादन बंद कर दिया है और आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26.06.2008 से अपनी फैक्टरी को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर प्रभावी पाटनरोधी उपायों की समीक्षा अनिवार्य है।

6. प्रक्रिया

आवेदकों द्वारा परिवर्तित स्थितियों जिनके कारण प्रभावी उपायों की समीक्षा अनिवार्य हो गई है, को दर्शाते हुए दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार परिवर्तित स्थितियों के मद्देनजर उपर्युक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9(क) के प्रावधान के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड I में दिनांक 16 जून, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम परिणाम तथा 19 जुलाई, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 75/2006 द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना अब समुचित है। समीक्षा में दिनांक 15.06.2006 की अधिसूचना सं. 14/18/2004-डीजीएडी के सभी पहलु शामिल हैं।

7. जांच की अवधि

वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2008 (12 महीने) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण की अवधि में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं जांच की अवधि शामिल होगी।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र एवं पद्धति में नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकती है।

9. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से “चालीस दिनों (40 दिनों)” के

भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथाचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

(Mid-term Review)

Subject : Initiation of Mid-term Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM) originating in or exported from the European Union, USA, China PR and Brazil.

No. 15/2/2009-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), vide Notification Number 14/18/2004-DGAD dated 15.6.2006 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I dated the 16th June, 2006, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti dumping duty on imports of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber(EPDM) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil (hereinafter referred to as subject country).

And Whereas definitive anti dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No.75/2006-Customs dated 19th July, 2006.

2. Product Under Consideration

The product under consideration involved in the original investigation and also in the present review application is " Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber(EPDM)" originating in or exported from European Union, USA, China PR and

1224 GI/09-2

Brazil. The subject goods are classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading No.4002.70 at six digit level. However, Customs classification is indicative only and, in no way, binding on the scope of the proposed investigation.

The product under consideration in the present investigation is Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM). EPDM is a synthetic Rubber and technical specifications of EPDM are broadly governed by Ethylene, Propylene and Diene content, and Mooney Viscosity. With the variations in Ethylene, Propylene and Diene Content and for Mooney Viscosity, different grades of EPDM Rubber can be produced.

EPDM Rubber is primarily used in rubber profiles, automotive tyres and tubes, cables, hoses and moulded items used in the automobile parts. The changes in Ethylene, Propylene and Diene content and Mooney Viscosity and other characteristics will merely modify the general property for which EPDM is consumed. EPDM Rubber can be of various grades and can be supplied in various forms. This investigation covers all grades of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated Diene Rubber (EPDM), in all grades and all forms.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti dumping duty. The All India Rubber Industries Association and Automotive Tyre Manufacturers Association have represented that EPDM is one of the key raw materials used by the tyre and non-tyre sectors. Although the sole manufacturer of the product viz., M/s. Unimers India Ltd has suspended production of the same since February-March, 2007 and is unlikely to resume production, the anti-dumping duty on the subject goods still continues affecting the competitiveness of the tyre and non-tyre sector goods. In view of the above, they have requested for an immediate withdrawal of anti-dumping duty on EPDM.

M/s. Unimers India Ltd., Mumbai has also intimated that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the provisions of The ID Act, 1947 with effect from 26.6.2008.

In view of the above circumstances, the Designated Authority considers that the mid-term review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Rule 23 of AD Rules and Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

4. Countries involved

The countries involved in the present investigations are European Union, USA, China PR and Brazil.

5. Grounds for Review

The petitioners viz., All India Rubber Industries Association and Automotive Tyre Manufacturers Association in their petitions have claimed that the sole manufacturer of EPDM i.e. M/s. Unimers India Ltd., has suspended production since long and EPDM being a critical input for the tyre and non-tyre sector, the anti-dumping duty imposed on the subject goods should be withdrawn with immediate effect to avoid unnecessary cascading effect on the cost of the tyre and non-tyre products. Further, M/s. Unimers India Ltd., Mumbai has also intimated that they have suspended production of EPDM Rubber and declared formal permanent closure of their factory as per the provisions of The ID Act, 1947, with effect from 26.6.2008. In view of the above circumstances a review of anti dumping measures in force is necessary.

6. Procedure

Having regard to the information provided by the applicants indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated authority now considers that a mid-term review of the final findings notified vide No. 14/18/2004-DGAD dated 15.6.2006 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I dated the 16th June, 2006, and the Definitive anti dumping duty imposed by Customs Notification No.75/2006 dated 19th July, 2006 is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra. The review covers all aspects of Notification No. 14/18/2004-DGAD dated 15.6.2006.

7. Period of Investigation

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present mid-term review is January to December, 2008 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 & POI.

8. Submission of Information

The exporters in subject country, their government through their Embassy in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation, in the prescribed form and manner within the time limit set out below:

9. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than "Forty Days (40 days)" from the date of letter of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

1224 GI/09-3